an>

Title: Need to set up paddy purchase centres in the country especially in Bihar in a time-bound manner.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदया, भारत किसानों का देश है, जहां 80 फीसदी किसान गांवों में बसते हैं, किंतु उनकी हालत फटेहाल है। देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार में किसानों के लिए धान क्रय केंद्र राज्य सरकार द्वारा काफी विलम्ब से खोले जाने के कारण लाखों किसानों का धान अधिप्राप्ति नहीं हो पा रहा है। बिहार में 15 नवम्बर, 2014 से धान क्रय केंद्र खुलना था, लेकिन जनवरी के अंत और फरवरी के प्रथम सप्ताह में खोला गया है, लेकिन वह भी व्यवस्थित नहीं चल रहा है। किसानों के बीच अफरा-तफरी मची हुई है, जिससे अधिकांश किसानों को शादी-विवाह तथा अन्य आवश्यक कार्यवश बिचौलियों एवं साहूकारों के यहां बाध्य हो कर औने-पौने भाव में काफी कम कीमत पर धान बिक्री करना पड़ रहा है। यहां तक कि उन्हें लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता है। सरकार द्वारा समय पर धान का समर्थन मूल्य 1660 रुपये प्रति क्विंटल प्राप्त नहीं होने के कारण किसानों द्वारा महाजनों का सूद चुकाना तो दूर खाने के भी लाले पड़े हुए हैं।

मेरा संसदीय क्षेत्र बक्सर शाहबाद धान का कटोरा कहलाने वाला आज कटोरा ले कर भीख मांगने की स्थिति में है। प्रशासनिक स्तर पर धान क्रय में काफी भ्रष्टाचार व्यापत है। यही हालत उत्तर बिहार एवं मध्य बिहार के अंतर्गत मगध एवं भागलपुर क्षेत्र के किसानों की है। किसान आत्महत्या करने के लिए विवश है एवं सभी किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य प्राप्त हो, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था करने का तथा एलपीसी के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से समर्थन मूल्य सरकार द्वारा दिया जाए, साथ ही पंचायत स्तर पर अप्रैल 2015 तक धान क्रय केंद्र की अवधि बढ़ाई जाए। राज्य में रबी फसल हेतु यूरीया खाद का आबंटन कम होने के कारण किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खाद की कालाबाजारी धड़ल्ले के साथ जारी है।

माननीय अध्यक्ष : आप केवल पेडी सेन्टर बढ़ाने की बात बोलिए।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: यहां तक कि 300 रुपए प्रति बोरा खाद की जगह 500-600 रुपये प्रति बोरा खाद ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है और कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है। इसलिए राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह कालाबाजारी पर प्रतिबंध लगाए और किसानों को खाद का आबंटन अधिक से अधिक किया जाए।